(b) whether due to this residents of the area are facing great hardship and acute shortage of milk and the private dairy owners are fleecing the general public by charging exorbitant prices;

(c) whether Government propose to open some DMS outlets/booths especially in Sector-3 of Rohini to supply milk in the area; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM (a) to (d) DMS has already opened eleven booths in Rohni and is making suitable supplies of milk keeping in view the demand.

As regards opening of DMS outlet$booth in Sector-3, Rohini, it may be stated that there is already one booth in this sector. The Residents Welfare Association in Sector 3, Rohini have, however, suggested opening of a new booth. They have been requested to make available rent free suitable accommodation to facilitate the opening of one more new booth by DMS.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे गए गेहूं की मात्रा

7160. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1993 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची गई गेहूं की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में कम थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष, 1993–94 में सरकार द्वारा गेहूं की खरीद भी पिछले वर्षों की तुलना में अधिक थी;

(ग) यदि हां, तो क्या गेहूं की अधिक खरीद तथा कम बिक्री के कारण भारतीय खाद्य निगम के समक्ष भंडारण की समस्या गंभीर हो गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या रबी फसल में गेहूं की सरकारी खरीद के बाद इस समस्या के और अधिक गंभीर होने की संभावना है ;

(च) यदि हां, तो सरकार गेहूं के भंडारण को सीमित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का विचार रखती है ;

(छ) क्या सरकार गेहूं के निर्यात पर भी विचार रखती है ; और

(ज) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (च) जी, नहीं । यह कहना सही है कि अधिक वसूली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए कम सप्लाई करने के कारण भारतीय खाद्य निगम को 1993–94 में भण्डारण समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि :—

(1) भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय रहते भण्डारण स्थान के लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर लिए गए थे । 1993–94 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने रबी फसल का भण्डारण करने के लिए 44 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता किराए पर ली थी ।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक खुली बिक्री के जरिए लगभग 30 लाख मीटरी टन गेहूं की बिक्री की गई है ।

(3) रबी मौसम 1993–94 के दौरान, निगम के पास निम्नलिखित भण्डारण क्षमता खाली थी :—

(आंकड़े मीटरी टन में)

1–4–93	74 लाख
1–5–93	63 लाख
1–6–93	42 लाख

अनुमान है कि रबी 1994 के दौरान लगभग 125 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली होगी । रबी फसल से खरीदे गए गेहूं के स्टाक के भण्डारण के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर लिए गए हैं । इसके अलावा, निगम ने सभी वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धको/जोनल प्रबन्धकों को उस क्षेत्र में स्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्षमता (ढकी हुई और कैप) किराए पर लेने की शक्तियां प्रदान की हैं । अत: वहां भण्डारण की कोई समस्या नहीं होगी । तथापि, निगम इस संबंध में सभी प्रयास कर रहा है और रबी स्टाक पर गहरी निगरानी रख रहा है ।

(छ) और (ज) भारतीय खाद्य निगम से सुगम स्टाक स्थिति को दृष्टि में केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के संबंध में एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल का निर्यात करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में अपना जायजा लगाते हुए एक नोट प्रस्तुत किया है । सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का निर्यात करने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

News item 'CWC strikes deals with corporates'

7161. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report which appeared in the 'Economic Times' dated the 29th March, 1994 under the caption "CWC strikes deals with corporates";

(b) if so, what are the reasons for this shift in policy;

(c) what are the details of the scheme including the terms and conditions thereof; and

(d) whether some agreements have already been entertd into in this regard; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes, Sir. There is no shift in the policy of Central Warehousing Corporation. The Corporation provides storage facilities for agricultural produce, foodgrains fertilisers, notified commodities such as industrial and consumer goods in its Warehouses. The companies referred to in the newspaper report have only kept their goods in the warehouses belonging to the Central Warehousing Corporation.

(c) and (d) There is no scheme as such. However, the Central Warehousing Corporation has entered into long term agreements with some private companies for storing their commodities/products in the warehouses of the Corporation. It has been stipulated that though the godowns will be used by the companies, the security for the godowns will be provided by Central Warehousing Corporation. The stocks will be kept in the godowns under the double locking system—one by Central Warehousing Corporation and the other by the depositors. The Insurance and accounting of the stocks will be that of the companies themselves. By providing such storage facilities, the Corporation has been able to augment its income.

गेहूं के निर्यात के संबंध में भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव

7162. श्री सोमपाल :
श्री शारदा महन्ती :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम चालू वर्ष में गेहूं के निर्यात पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो निर्यात किए जाने वाले गेहूं की मात्रा कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानत: कितनी कीमत प्राप्त होने की संभावना है ;